अब्दुल वहाब अन्सारी

बनाम्

बिहार राज्य और एक अन्य

अक्टूबर 17,2000

[जी. बी. पटनायक, एम. बी. शाह और एस. एन. फुकान, न्यायाधीशगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 197 (1)

लोक सेवक-आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते समय अपराध होना/करना-उपयुक्त प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी के संबंध में याचिका का संज्ञान-किस स्तर पर मुद्दा उठाया गया है, कार्यवाही के किसी भी चरण में उठाया जा सकता है और आरोप तय होने तक ऐसी याचिका लेने के लिए प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

लोक सेवक अतिक्रमण-हटाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया। अतिक्रमण स्थल पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोलीबारी करने का आदेश जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मौत और अन्य घायल हो गया-इसके अलावा, लोक सेवक द्वारा खुली गोलीबारी का आदेश देने की कार्रवाई अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में थी-धारा 197 के प्रावधान लागू होते हैं और उचित सरकार से पूर्व मंजूरी के बिना उसके खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है-सरकार-इस प्रकार, दंडाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी, एक लोक सेवक को कुछ अतिक्रमण हटाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था। जब अपीलार्थी उस स्थान पर गया अतिक्रमण, हथियारों से लैस कई उपद्रवियों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। अपीलार्थी ने उचित चेतावनी देने के बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया। इस तरह की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मृतक के पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी ने

भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 380, 427, 504, 147, 148 और 149 साथ ही साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के के तहत अपराध किया है। दंडाधिकारी ने यह मानते हुए कि अपीलार्थी के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया था, एक गैर-जमानती वारंट जारी किया, अपीलार्थी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि चूंकि वह अपने आधाकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था इसलिए संहिता की धारा 197(1) के प्राधिकारी के तहत उपयुक्त प्राधिकरी से पूर्व मंजूरी के बिना उसके खिलाफ कोई संज्ञान नहीं किया जा सकता है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन का यह कहते हुए निपटारा कर दिया कि पूर्व मंजूरी के संबंध में याचिका आरोप तय करने के समय उठाई जा सकती है।

इसलिए वर्तमान अपील अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत, अदालत को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के अलावा आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए अपराध का संज्ञान लेने से रोक दिया गया है, और ऐसा नहीं है और अभियुक्त के लिए आरोप तय करने के चरण तक प्रतीक्षा करने का कोई औचित्य नहीं है और इसलिए, उच्च न्यायालय ने कानून में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करने में गलती की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा

माना: 1.1 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं ठहराया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 (1) के तहत पूर्व मंजूरी के संबंध में याचिका केवल आरोप तय करने के चरण में ही उठाई जा सकती है, न कि उससे पहले। [754-सी)

1.2 सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अपराध का संज्ञान लेने में न्यायालय के लिए एक पूर्व शर्त है, यदि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में एक कार्य कहा जा सकता है, तो प्रश्न संज्ञान लेने के मामले में दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र को छूता है और इसलिए, इसकी आवश्यकता नहीं है कि

किसी अभियुक्त को आरोप तय होने तक ऐसी याचिका लेने के लिए इंतजार करना चाहिए। (752-सी)

सुरेश कुमार भीकमचंद जैन बनाम पांडे अजय भूषण और अन्य, (1998) 1 एस. सी. सी. 205; अशोक साहू बनाम गोकुल सैकिया और एक अन्य, (1990) सप।एस. सी. सी. 41 और पी. साहा और अन्य बनाम एम. एस. कोचर, (1979) 4 एस. सी. सी. 177, पर भरोसा किया।

बीरेंद्र के. सिंह बनाम बिहार राज्य, जे. टी. (2000) 8 एस. सी. 248 ने खारिज कर दिया।

2. संहिता की धारा 197 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, अभियुक्त द्वारा किए गए कथित अपराध का आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से कुछ लेना-देना होना चाहिए, या किसी तरह से संबंधित होना चाहिए। तत्काल मामले में, अनुमंडलीय दंडाधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुलिस बल के साथ उपस्थित रहने और प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया था और भीड़ को नियंत्रित करने के अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान जब उसने गोली चलाने का निर्देश दिया था, तो यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि गोली चलाने का आदेश उसे प्रदत्त शक्ति और दंडाधिकारी के आदेशों के तहत उस पर लगाए गए कर्तव्य का प्रयोग था और इस मामले को देखते हुए धारा 197 (1) के प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं।

मान लीजिए कि कोई मंजूरी नहीं होने के कारण, दंडाधिकारी द्वारा लिया गया संज्ञान कानूनी रूप से गलत है और जब तक कि इसे अपीलार्थी के लिए रद्द नहीं किया जाता है, यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। [754-डी; 755-सी, डी, ई]

माताजोग डोबे बनाम एच. सी. भारी, (1955) 2 एस. सी. आर. 925, इसके बाद आया।

गौरी शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य और एक अन्य, [2000) 5 एस. सी. सी. 15 और सुरेश कुमार भीकमचंद जैन बनाम पांडे अजय भूषण और अन्य, [19981 1 एस.सी.सी. 205, पर भरोसा किया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 885/2000

पटना उच्च न्यायालय के 16.11.99 दिनांकित निर्णय और आदेश से 1995 का आपराधिक एम. संया- 18954

अपीलार्थी की ओर से प्रदीप रंजन तिवारी, संतोष कुमार और राकेश के. शर्मा।

उत्तरदाताओं की ओर से बी. बी. सिंह और एस. के. सिन्हा।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पटनायक के द्वारा दिया गया ।

निर्णय

अनुमति दी गई।

अपीलार्थी एक लोक सेवक है और अनुमंडलीय दंडाधिकारी ने उससे स्पष्टीकरण मांगा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद प्रश्नगत अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा है। उक्त अनुमंडलीय दंडाधिकारी ने 25 जून, 1993 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को कार्य दंडाधिकारी और एक श्री विनोद पाल सिंह को पुलिस बल के वरिष्ठ प्रभारी दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त किया, जिन्हें प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता थी। उक्त अपीलार्थी ने अतिक्रमण स्थल का दौरा किया और अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया और 16.7.1993 को अतिक्रमण आंशिक रूप से हटाने में सक्षम हुआ और अपने वरिष्ठ अधिकारी को उक्त तथ्य की सूचना दी, लेकिन 17.7.1993 को जब अपीलार्थी सशस्त्र बल के साथ अतिक्रमण स्थल पर पहुंचा, तो हथियारों से लैस कई उपद्रवियों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और जैसे ही स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, उचित चेतावनी देने के बाद,

अपीलार्थी को गोली चलाने का आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ा और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इस तरह की गोलीबारी के कारण, व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई और दो अन्य घायल हो गए और अपीलार्थी ने तब घटना के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी को एक सूचना भेजी। मृतक के पुत्र, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 है, ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें अपीलार्थी पर भा.दं.सं. की धारा 302, 307, 380, 427, 504, 147, 148 और 149 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अपने दिनांक 24.11.1995 के आदेश से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं कि अभियुक्त के खिलाफ धारा 302,307,147,148,149 और 380 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है और इसलिए, उन्होंने अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की यह भी राय थी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के प्रावधान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे। इसके बाद अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 की उप-धारा (2) के तहत उपयुक्त सरकार की मंजूरी के बिना कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। अपीलार्थी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुसार अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। तथापि, उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना और यह राय रखे बिना कि सभी प्रश्न आरोप-निर्धारण के समय उठाए जा सकते हैं, अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन और इसलिए इस न्यायालय में वर्तमान अपील का निपटारा कर दिया। यह कहा जा सकता है कि मुसलमान निवासियों के दो समूहों के बीच विवाद था, एक समूह ने दूसरे के खिलाफ मस्जिद से संबंधित संपत्ति के अतिक्रमण के बारे में शिकायत की थी और अपीलार्थी ने अंचल निरीक्षक के रूप में, उक्त शिकायत के आधार पर मामले की जांच की थी और एक विस्तृत जांच के आधार पर, एक निष्कर्ष पर पहुंचा था कि स्थल पर स्थिति अस्थिर थी, जिसके लिए 27 मार्च, 1991 को धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया था। इसके बाद अपीलार्थी ने अतिक्रमण हटाने के लिए

अतिक्रमणकारियों से कई प्रश्नगत किए और अंततः उनुमंडलीय दंडाधिकारी, औरंगाबाद ने 25 जून, 1993 के अपने आदेश द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल के उपयोग के लिए अपीलार्थी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया। जब वर्तमान अपील हमारे समक्ष सूचीबद्ध की गई थी, तो बीरेंद्र के. सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। जे. टी. 2000 (8) एस. सी. 248 में सूचित बिहार राज्य को हमारे समक्ष रखा गया था और यह तर्क दिया गया था कि धारा 197 Cr.P.C के प्रावधानों की प्रयोज्यता का सवाल आरोप तय करने के चरण में उठाया जा सकता है और इसलिए, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त निर्णय निस्संदेह प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्क का काफी हद तक समर्थन करता है, लेकिन चूंकि हमें कानून के उपरोक्त उच्चारण की शुद्धता पर संदेह था, इसलिए मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था और इस तरह हम मामले के सत्र में हैं।

अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 की सरल भाषा में, जब अदालत को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के अलावा अपराध का संज्ञान लेने से प्रतिबंधित किया जाता है, अगर यह स्थापित हो जाता है कि कथित अपराध उसके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए किया गया था, तो अभियुक्त के लिए आरोप तय करने के चरण तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करने का कोई औचित्य नहीं है और इसलिए उच्च न्यायालय कानून में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करने में त्रुटियां में था। मामले के तथ्यों पर, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार घटना स्थल पर मौजूद था और उस अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता थी और जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो उसने गोलीबारी का आदेश दिया, अतिक्रमण हटाने के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए और इस तरह की गोलीबारी के अनुसार, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दो व्यक्ति घायल हो गए, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अर्थ के भीतर आरोपी अपीलार्थी के आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन से

संबंधित पुलिस बल का उपयोग और परिणामस्वरूप, प्रश्नगत प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, अदालत एक निजी शिकायत के आधार पर अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती थी।

शिकायतकर्ता-प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस. के. सिन्हा के साथ-साथ बिहार राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस. के. सिन्हा ने निष्पक्ष रूप से कहा कि बीरेंद्र के. सिंह के मामले में इस न्यायालय के फैसले को बहुत व्यापक रूप से कहा गया है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद उठाने के लिए अभियुक्त को आरोप तय होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के प्रावधानों के लागू होने का संबंध है, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हालांकि बिहार राज्य की ओर से पेश श्री बी. बी. सिंह ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप की गंभीरता स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि अपीलार्थी अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था जब उसने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाने का निर्देश दिया था और इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के प्रावधान लागू होंगे। दूसरी ओर शिकायतकर्ता-प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सिन्हा ने तर्क दिया कि शिकायत किए गए कार्य को अपीलार्थी के आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में नहीं माना जा सकता है और इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के प्रावधानों का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

बार में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को देखते हुए, हमारे विचार के लिए दो प्रश्न उठते हैं: 1. यह मानते हुए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के प्रावधान लागू होते हैं, आरोपी किस स्तर पर ऐसी याचिका दायर कर सकता है? क्या यह संज्ञान लेने और प्रक्रिया जारी होने के तुरंत बाद है या यह केवल तभी है जब न्यायालय बीरेंद्र के. सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित आरोप तय करने के चरण में पहुंच जाता है। 2. क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, क्या न्यायालय के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव है कि अपीलकर्ता अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था और इस तरह के कर्तव्य के निर्वहन के दौरान, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए

गोली चलाने का आदेश दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दो व्यक्ति घायल हो गए और किस स्थिति में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सकता है?

जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, धारा 197 के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के अलावा अपराध का संज्ञान लेने से प्रतिबंधित किया गया है। इस मुद्दे की बेहतर समझ के लिए, धारा 197 (1) को नीचे विस्तार से उद्धृत किया गया हैः धारा 197 (1) जब कोई व्यक्ति जो न्यायाधीश या दंडाधिकारी या लोक सेवक है या था जो सरकार द्वारा या सरकार की मंजूरी के अलावा अपने पद से हटाने योग्य नहीं है, उस पर अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का इरादा रखते हुए उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो कोई भी न्यायालय ऐसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय पूर्व मंजूरी के-(ए) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो नियोजित है या, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार के संघ के मामलों के संबंध में नियोजित कथित अपराध के समय था; (बी) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो नियोजित है या, जैसा भी मामला हो, कार्य के संबंध में नियोजित कथित अपराध के समय था।

सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अपराध का संज्ञान लेने में न्यायालय के लिए एक पूर्व शर्त है, यदि अभियुक्त द्वारा किए गए कथित अपराध को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में एक कार्य कहा जा सकता है, तो प्रश्न संज्ञान लेने के मामले में दंडाधिकारी के अधिकार क्षेत्र को छूता है और इसलिए, यह कोई आवश्यकता नहीं है कि एक अभियुक्त को आरोप तय होने तक इस तरह की याचिका लेने की प्रतीक्षा करें। सुरेश कुमार भीकमचंद जैन बनाम पांडे अजय भूषण और अन्य, 1998 (1) एस. सी. सी., 205 में, उस मामले में अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिबबल द्वारा इसी तरह का तर्क दिया गया था। उस मामले में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के आवेदन पर निर्णय दिया था कि धारा 197 के प्रावधान आकर्षित होते हैं। तर्क को खारिज करते हुए, इस अदालत ने कहा थाः

धारा 197 की उप-धारा (1) में निहित विधायी अधिदेश किसी न्यायालय को किसी अपराध का संज्ञान लेने से रोकता है, सिवाय उस मामले में संबंधित सरकार की पूर्व मंजूरी के, जिसमें शिकायत किए गए कार्य कथित रूप से किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए हैं या अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में होने का तात्पर्य है और ऐसे लोक सेवक को सरकार द्वारा या सरकार की मंजूरी के अलावा अपने पद से हटाने योग्य नहीं है, अदालत के अधिकार क्षेत्र को ही छूता है।यह कानून द्वारा आरोपित को, जारी की जा रही प्रक्रिया पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बाद, एक आवेदन द्वारा संज्ञान लेने से लगाया गया निषेध है, जो दर्शाता है कि धारा 197 (1) को आकर्षित किया गया है, केवल अदालत को अपनी त्रुटियां को सुधारने में सहायता करता है जहां अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया गया है जो उसके पास नहीं है।ऐसे मामले में अभियुक्त के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों और सामग्रियों को प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए जो वास्तव में स्वीकार्य हों, इस प्रश्न के निर्णय के लिए कि क्या वास्तव में धारा 197 का मामले में कोई आवेदन है।यह अब विवाद में नहीं है और इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में संकेत दिया गया है कि मंजूरी के प्रश्न पर कार्यवाही के किसी भी चरण में विचार किया जा सकता है।

न्यायालय ने आगे कहा थाः

संहिता की धारा 197 के लागू होने और वैध मंजूरी के बिना संज्ञान लेने के लिए अदालत की अधिकारिता के परिणामी निष्कासन का सवाल आनुवंशिक रूप से अभियुक्त की याचिका से अलग है कि शिकायत में किए गए कथन अपराध नहीं हैं और इस तरह संज्ञान के आदेश और/या आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए। उपरोक्त परिसरों में हमारी यह सुविचारित राय है कि एक अभियुक्त को प्रासंगिक दस्तावेजी सामग्री प्रस्तुत करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, जिसे बिना किसी औपचारिक प्रमाण के कानूनी रूप से देखा जा सकता है, इस रुख के समर्थन में कि शिकायत किए गए कार्य उसके अधिकार क्षेत्र या एक लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कथित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किए गए थे, जिससे उपयुक्त प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

अशोक साहू बनाम गोकुल सैकिया और एक अन्य 1990 (पूरक) एस. सी. सी. 41 के मामले में, इस अदालत ने कहा था कि संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी का अभाव कार्यवाही की स्थापना के खिलाफ एक निषेध है, और धारा की प्रयोज्यता को कार्यवाही के शुरुआती चरण में आंका जाना चाहिए और उस मामले में, अदालत ने दंडाधिकारी को आरोप तैयार करने से पहले मंजूरी के प्रश्न पर विचार करने का निर्देश दिया। एक अन्य मामले, पी. साहा और अन्य बनाम एम.एस कोचर 1979(4) एसीसी 177 में न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया था कि धारा 197 के तहत मंजूरी का प्रश्न कार्यवाही के किसी भी चरण में उठाया और विचार किया जा सकता है और इस प्रश्न पर विचार करने में कि अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता थी या नहीं, न्यायालय के लिए शिकायत में आरोपों तक ही सीमित रहना आवश्यक नहीं है, और उस समय जब प्रश्न उठाया जाता है और विचार के लिए आता है तब अभिलेख पर सभी सामग्री को ध्यान में रखा जाता है। ऐसी स्थिति होने के कारण, हमारी यह सुविचारित राय है कि बीरेंद्र के. सिंह के मामले जे. टी. 2000 (8) एस. सी. 248 में इस न्यायालय का निर्णय यह निर्देश देकर सही कानून निर्धारित नहीं करता है कि मंजूरी के प्रश्न पर आपत्ति आरोप तय करने के चरण में उठाई जा सकती है, न कि किसी पूर्व बिंदु पर।

दूसरे प्रश्न पर आते हुए, अब माताजोग डोबे बनाम एच. सी. भारी, 1955 (2) एस. सी. आर. 925 में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी देने के मामले में अभियुक्त द्वारा किए गए कथित अपराध का आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से कुछ लेना-देना होना चाहिए, या किसी तरह से संबंधित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अधिनियम और आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए; अधिनियम को कर्तव्य के साथ ऐसा संबंध रखना चाहिए कि अभियुक्त एक उचित दावा कर सके, लेकिन एक ढोंग या काल्पनिक दावा नहीं, कि उसने इसे अपने कर्तव्य के प्रदर्शन के दौरान किया था। उक्त मामले में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां कोई शक्ति प्रदत्त की गई है या कानून द्वारा या अन्यथा अधिरोपित कर्तव्य है, और

किसी भी सीमा या प्रतिबंधों द्वारा शक्ति के प्रयोग या कर्तव्य के प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से बाधित करने वाला कुछ भी नहीं कहा गया है, तो यह अभिनिर्धारित करना उचित है कि वह अपने साथ ऐसे सभी कार्यों को करने या ऐसे साधनों को नियोजित करने की शक्ति रखता है जो ऐसे निष्पादन के लिए उचित रूप से आवश्यक हैं, क्योंकि यह एक नियम है कि जब कानून किसी काम को करने का आदेश देता है, तो वह अपने आदेश को निष्पादित करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो, उसके प्रदर्शन को अधिकृत करता है। इस निर्णय के बाद इस न्यायालय ने सुरेश कुमार भीकमचंद जैन मामले, 1998 (1) एस. सी. सी. 205 में और गौरी शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य और ए. एन. आर., 2000 (5) एस. सी. सी. 15 के मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसले में यह निर्णय लिया। न्यायालय ने कहा था कि उपरोक्त मामले में वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए भी पूरी ताकत है क्योंकि उक्त मामले में कहा गया थाः

यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से अनुमंडलीय दंडाधिकारी के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमता में घटना स्थल पर मौजूद था और इस तरह के कर्तव्य का पालन करते हुए, उस पर उन कार्यों को करने का आरोप लगाया जाता है जो प्रतिवादी द्वारा दर्ज की गई शिकायत में निहित आरोपों की गंभीरता को दर्शाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किए बिना नहीं रखा जा सकता है कि अपीलार्थी के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा शिकायत किए गए कार्यों का अपीलार्थी के आधिकारिक कर्तव्य के साथ उचित संबंध है। अतः यह इस प्रकार है कि अपीलार्थी धारा 197 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान की गई मंजूरी के बिना आपराधिक कार्यवाही से प्रतिरक्षा का हकदार है।

हमारे लिए इस बिंदु पर प्राधिकारियों को गुणा करना आवश्यक नहीं है और उपरोक्त मामलों के अनुपात प्रश्नगत रखते हुए और शिकायत में बताए गए वर्तमान मामले के तथ्यों को लागू करते हुए, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अपीलकर्ता को उप-मंडल दंडाधिकारी द्वारा पुलिस बल के साथ उपस्थित रहने और अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया था और भीड़ को नियंत्रित करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, जब उसने गोली चलाने का निर्देश दिया था, तो

यह माना जाना चाहिए कि गोली चलाने का आदेश उसे दी गई शक्ति और दंडाधिकारी के आदेशों के तहत उस पर लगाए गए कर्तव्य का प्रयोग था और इस मामले में धारा 197 (1) के प्रावधान इन तथ्यों पर लागू होते हैं। मान लीजिए, कोई मंजूरी नहीं होने के कारण, दंडाधिकारी द्वारा लिया गया संज्ञान कानूनी रूप से गलत है और जब तक इसे अपीलार्थी के लिए रद्द नहीं किया जाता है, यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हैं।

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।